शहजादखान महबूबखान पठान

बनाम

गुजरात राज्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 1592)

5 अक्टूबर, 2012

[पी. सतशिवम और रंजन गोगोई, जे. जे.]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एसएस-8 (ग), 21 और 29-अभियुक्त-अपिलार्थी को वाणिज्यिक मात्रा में ब्राउन शुगर (मादक पदार्थ) ले जाने के लिए निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गया और अपीलार्थी को 15 साल की और. आई. की सजा सुनाई गई। सजा कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी पहली बार अपराधी थे और पहले के अवसरों पर समान प्रकृति के अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे कोई पूर्ववृत नहीं था। उसी को देखते हुए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, उनकी सजा को घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया, जो सम्बन्धित प्रावधानों के तहत न्यूनतम निर्धारित सजा है। अधिनियम-सरकारी अधिसूचना संख्या एसअ. 1055(ई) दिनांक 19.10.2001-वाक्य/सजा।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एसएस. 8 (सी), 21 और 29- अभियुक्त-अपीलार्थी को व्यावसायिक मात्रा में ब्राउन शुगर (मादक पदार्थ) ले जाने के लिए निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गया, 15 साल की और. आई. की सजा सुनाई गई और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया । 3 साल के लिए और .आई. से गुजरना, पूर्व निर्धारित सजा में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रार्थना की गई- अभिनिर्धारित जब पूर्वनिर्धारित सजा दी जाती है, तो एक व्यक्ति को कारावास से गुजरना पड़ता है क्योंकि या तो वह जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ है या करने से इनकार करता है, ऐसे स्थिती में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जुर्माना न अदा करने पर कारावास भुगतने का आदेश् देने से पहले अपराध की प्रकृति, जिन परिस्थितियों में यह किया था, अपराधी की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखें। वर्तमान मामले में, परिस्थितियाँ ध्यान में रखतें हुए उन्हें ऐसा करना होगा कि अपीलार्थी बहुत गरीब हैं और वे अपने परिवार को भरण-पोषण करते हैं, यह उनका पहला अपराध था और यदि वे विचारण न्यायालय के आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असफल होते हैं, तो उन्हें मूल सजा की अवधि के अलावा 3 साल की अवधि के लिए जेल में रहना होगा; गंभीर पूर्वाग्रह होगा न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी जो निर्दोष हैं- न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि यह है आदेश दिया कि रुपये के जुर्माने

के भुगतान की चूक पर डेढ़ लाख, अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय के आदेश और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 3 वर्ष के बजाय 6 महीने के लिए और आई. से गुजरने का निर्देश दिया जाता है। सरकारी अधिसूचना संख्या एसओ.1055(ई) दिनांकित 19.10.2001- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, एस. 30 -दंड संहिता, 186, एस. एस. 63 से 70 तक- सजा/सजा - मुख्य वाक्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2012] 8 एस.सी. और .

एक गुप्त सूचना पर, नारकोटिक सेल ने दोनों अपीलार्थी को कथित रूप से 500 ग्राम ब्राउन शुगर डी (मादक पदार्थ) ले जाने के लिए गिरफ्तार किया। निचली अदालत ने सरकारी अधिसूचना संख्या एसओ 1055 (ई) दिनांकित 19.10.2001 और मादक द्रव्यों के प्रावधान और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) की मात्रा "वाणिज्यिक मात्रा" के अन्तर्गत आती है और अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 (सी), 21 और 29 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 15 वर्षों के कठोर कारावास (और. आई.) की सजा सुनाई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य से हैं और व्यापार करने के लिए गुजरात राज्य में इतनी व्यावसायिक मात्रा में ब्राउन शुगर ले जा रहे थे, विचारण न्यायालय ने उन पर 1.5 लाख रुपये का

जुर्माना भी लगाया गया और प्रत्येक को, मुख्य रूप से आगे 3 साल के लिए और . आई. से गुजरना होगा। उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलों द्वारा आदेश को बरकरार रखा।

अपीलकर्ताओं ने दोषसिद्धि को गंभीरता से चुनौती नहीं दी हालाँकि, सजा को कम करने का अनुरोध किया और निचली अदालत द्वारा दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई पूर्वनिर्धारित सजा में संशोधन के लिए भी प्रार्थना की।

न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए,

1. प्रार्थना की गई सीमित राहत को देखते हुए और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में रखी गई प्रासंगिक और स्वीकार्य सामग्रियों पर विचार करते हुए, दोषसिद्धि से संबंधित निष्कर्ष को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है। **[पैरा 7] [1183-एफ]**

2.स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 21 और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा 10 वर्ष है जो जुर्माने के साथ 20 वर्ष तक बढ़ सकता है। मौजूदा मामलें में, दोनों अपीलार्थी पहली बार अपराधी हैं और पहले के अवसरों पर समान प्रकृति के अपराध में उनकी संलिप्तता को कोई इतिहास नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हुए, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, सजा

को घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम निर्धारित सजा है। **[पैरा 8,9] [1184-सी, एफ-जी]**

बलविंदर सिंह बनाम सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क **(2005) 4 एस. सी. सी. 146**-पर निर्भर था।

पूर्वनिर्धारित सजाः

3.1. जुर्माना भुगतान न करने पर कारावास की अवधि कोई सजा नहीं है। यह एक जुर्माना है जो किसी व्यक्ति को जुर्माने का भुगतान न करने लगता है। यदि सजा दी जाती है तो, निस्संदेह एक अपराधी को तब तक भुगतना पड़ता है जब तक कि न्यायिक में इसे आंशिक या संपूर्ण रूप से संशोधित या परीवर्तित न किया जाए हालाँकि, जुर्माने के भुगतान न करने पर कारावास का आदेश अलग आधार पर है। जब इस तरह की पूर्वनिर्धारित सजा दी जाती है, तो किसी व्यक्ति को कारावास से गुजरना पड़ता है क्योंकि या तो वह जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है या जुर्माने की राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है। तदनुसार, वह जुर्माने की इतनी राशि का भुगतान करके जुर्माना न चुकाने पर कारावास से हमेशा बच सकता है। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय का कर्तव्य है की जुर्माने का भुगतान न करने पर अपराधी को कारावास भुगतने का आदेश देने से पहले न्यायालय अपराध की प्रकृति को ध्यान में

रखते हुए, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, अपराधी की स्थिति और उससे पहले के अन्य प्रासंगिक विचारो को ध्यान में रखना चाहिए। और इ.पी.सी. की धारा 63 से 70 के प्रावधान यह स्पष्ट करते है कि जुर्माना राशि कठोर या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए इसके अलावा जहां कारावास की अवधि अधिक लगाई जाती है, वहां असाधारण मामलों को छोड़कर जुर्माना अधिक नहीं लगाया जाना चाहिए। **[पैरा 12] [1190-ई एच; 1191-ए]**

3.2. सी. और. पी. सी. धारा 30 में जुर्माने की चूक में कारावास की सजा का प्रावधान है। और सी. पी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (1) का खंड (बी) न्यायालय को कारावास की अवधि के 1/4 तक जुर्माने की चूक में कारावास का निर्णय देने के लिए अधिकृत करती है, जिसे न्यायालय अपराध के लिए सजा अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। हालांकि, परिस्थितिया को ध्यान में रखकर विचार करते हुए, अर्थात अपीलार्थी-अभियुक्त बहुत गरीब हैं और यदि वे निचली अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं में, उन्हें मूल अवधि के अतिरिक्त 3 वर्ष की अवधि के लिए जेल में रहना पड़ता है। जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थता के कारण, गंभीर पूर्वाग्रह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यो के लिए भी होगा जो निर्दोष हैं। न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि यदि यह आदेश दिया जाता है कि डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भुगतान की चूक में अपीलार्थियों को निचली

अदालत के आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अनुसार 3 साल के बजाय 6 महीने के लिए और आई. से गुजरना होगा।**[पैरा 14] [1191-डी; 1192 ए-डी]**

शांतिलाल बनाम। एम. पी. राज्य (2007) 11 एस. सी. सी. 243: 2007 (10) एससी और 727-पर निर्भर।

निष्कर्षः

4. अभिलिखित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और और. आई. से गुजरने के लिए अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंड 15 वर्ष को संशोधित कर 10 वर्ष कर दिया गया है। भुगतान का आदेश प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माने को भी बरकरार रखा जाता है लेकिन आदेश है कि जुर्माने का भुगतान न करने पर, अपीलकर्ताओं को 3 साल के लिए और. आई. से गुजरना होगा, जिसे घटाकर 6 महीने के लिए और आई. कर दिया गया है। चूंकि जुर्माने के भुगतान में चूक के सम्बन्ध में सजा की संशोधित अवधि के अनुसार अपीलकर्ता पहले ही लगभग 12 साल कारावास में काट चुके हैं, इसिलए उन्हें जेल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थियों को तुरंत स्वतंत्रता कर दिया जाएगा जब तक कि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो। हालाँकि, किसी भी कारण से यदि अपीलकर्ताओं ने सजा की संशोधित अवधि पूरी नहीं की है, तो उन्हें ऊपर दर्शाई गई अवधि के बाद रिहा कर दिया जाएगा। **[पैरा 15] [1192-ई-जी]**

संदर्भ के लिए कानून

(2005)4 एस.सी.सी. 146 पर आश्रित पैरा 8

2007(10)एस.सी. और. 727 पर आश्रित पैरा 11

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या-1592/2012

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या-11/ 2002 के निर्णय और आदेश दिनांक 8.7.2002 से

एवं सी. और .एल. 2012 की अपील सं. 1593

अपीलार्थी की ओर से डॉ. सुशील बलवाड़ा

के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, हेमंतिका वाही उत्तरदाता

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

पी. सतशिवम, जे.

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. अनुमति दे दी गई।

3. ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा 2002 की आपराधिक अपील संख्या 11 और 75 में पारित अंतिम फैसले और आदेश दिनांक 08.07.2002 के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज

कर दिया था। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद शहर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 381/ 2000 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2001 पुष्टि की।

4. संक्षिप्त तथ्य

दिनांक 04.09.2000 को, एक गुप्त सुचना पर नारकोटिक सेल, पुलिस भवन, गांधीनगर, गुजरात ने दो व्यक्तियों शहजादखान महबूबखान पठान और नरेंद्रसिंह चंद्रशेखर राय (अपीलकर्ता) को 500 ग्राम ब्राउन शुगर (मादक पदार्थ) के साथ गिरफ्तार किया, जब वे कालुपुर रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद में सर्वोदय एक्सप्रेस में दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए रतलाम तक यात्रा कर रहे थे।

तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (संक्षेप में एन. डी. पी. एस. एक्ट) के तहत मामला दर्ज करने के बाद नमूने फोरेंसिक विज्ञानप्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) को परीक्षण के लिए भेजे गए थे।

19.12.2000 को, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और सन 2000 के सत्र मामला सं. 381 के रूप में क्रमांकित था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद शहर, ने सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 1055 (ई) दिनांक 19.10.2001 और

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधान पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) की मात्रा "वाणिज्यिक मात्रा" शीर्षक के अंतर्गत आती है और अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8 (सी), 21 और 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और उन्हे 15 वर्ष के कठोर कारावास (और .आई.) भुगतने की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और व्यापार करने के लिए गुजरात राज्य में इतनी व्यावसायिक मात्रा में ब्राउन शुगर ले जा रहे थे, प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, साथ ही उन्हें आगे 3 साल के लिए और .आई. से गुजरना होगा।

व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामला दायर किया अपील संख्या 11 और 75 वर्ष 2002 दायर की। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 08.07.2002 के आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त अपीलों को खारिज कर दिया। इस पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से अलग-अलग अपीलें दायर की हैं।

5.अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सुशील बलवाड़ा और प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुश्री के. एनाटोली सेमा को सुना।

6.उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए तथ्यों पर विचार करते हुए, दोषसिद्धि को गंभीरता से नहीं लिया है हालाँकि, उम्र और गरीबी सहित पहलुओं विभिन्न पहलु को ध्यान में रखते हुए, सजा में कमी के लिए प्रार्थना की गई इसके अलावा विद्वान अधिवक्ता ने प्रचार किया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद शहर द्वारा प्रदत्त और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई पूर्वनिर्धारित सजा में संशोधन के लिए प्रार्थना की।

7. प्रार्थना की गई सीमित राहत को देखते हुए और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में रखी गई प्रासंगिक और स्वीकार्य सामग्रियों पर विचार करते हुए दोषसिद्धि से संबंधित निष्कर्ष को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, हम एतद्द्वारा उसकी पुष्टि करते है।

सजाः

8. सजा के सवाल पर आते हैं, यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थियों पर 500 ग्राम की मात्रा में ब्राउन शुगर रखने का आरोप लगाया गया था जो "वाणिज्यिक मात्रा" के अन्तर्गत आती है। सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ े.1055 (ई) दिनांक 19.10.2001 के अनुसार एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21 (सी) के संदर्भ में इस पर विचार करना आवश्यक है। विचारण न्यायाधीश, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि

अपीलकर्ता मध्य प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य में ऐसी वाणिज्यिक मात्रा में ब्राउन शुगर की ले जाने के लिए 15 साल और आई. की सजा सुनाई और उन्हें डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया, साथ ही उन्हें आगे 3 साल के लिए और.आई. से गुजरना होगा। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8 (सी), 21 और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निस्संदेह, निर्धारित न्यूनतम सजा 10 साल है, जो जुर्माने के साथ 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में बलविंदर सिंह बनाम सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (2005) 4 एससीसी 146 मामलें में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करना उपयोगी है। अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 18,22,23,25,28,29 और 30 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी (आई.पी.सी.) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इस न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी पहली बार उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया (पर जोर दिया गया), दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, एन.डी.पी.एस. अधिनियम और आईपीसी के तहत अपराधों के लिए सजा को 14 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया।

9. यह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि दोनों अपीलार्थी पहली बार अपराधियों हैं और पहले के अवसरों पर समान प्रकृति के अपराध में संलिप्तता का कोई अतीत पूर्ववृत्त नहीं है। यह हमारे संज्ञान में लाया गया,

जिस पर राज्य के लिए विद्वान अधीवक्ता ने भी कोई आपत्ती नहीं जताई है कि कि आज की तारीख तक अपीलार्थियों ने लगभग 12 साल जेल में काटे है, इसे ध्यान में रखते हुए और इस अदालत के फैसले के आलोक में, बलविंदर सिंह (सुप्रा) के मामलें में, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए हम सजा को घटाकर 10 कर देते हैं, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत न्यूनतम निर्धारित सजा है।

पूर्वनिर्धारित सजाः

10. अपीलार्थियों के अगले दावे अर्थात पूर्वनिर्धारित सजा पर आते हुए, विचारण न्यायाधीश ने इस तथ्य सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए कि अपीलकर्ता ब्राउन शुगर की वाणिज्यिक मात्रा व्यापार करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य में ले जा रहे थे, प्रत्येक पर 1.5 लाख लाख रुपये का जुर्माना लगाया, पूर्वनिर्धारित रूप से 3 साल के लिए और .आई. से गुजरने का आदेश दिया गया।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधीवक्ता के अनुसार, पूर्वनिर्धारित सजा यानी 3 साल, बहुत कठोर है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर ऐसे सजा देनी चाहिए। उसी को देखते हुए, उन्होंने शांतिलाल बनाम एम.पी. राज्य (2007) 11 एस.सी.सी. 243 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, कारावास पर विचार किया, जिसमें इस न्यायालय का ने आई.पी.सी. और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(संक्षेप में कोड) के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में जुर्माने का भुगतान करने में चूक पर कारावास पर विचार किया था और इसे निम्नानुसार रखा गया हैः

"31.....जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की अवधि कोई सजा नहीं है। यह एक जुर्माना है जो किसी व्यक्ति के जुर्माना न चुकाने पर लगता है।

सजा एक ऐसी चीज है जिससे एक अपराधी को जब तक गुजरना पड़ता है जब तक कि इसे अपील में या पुनरीक्षण में या अन्य उचिन न्यायिक कार्यवाही में या "अन्यथा" आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द या माफ नहीं किया जाता। जुर्माने के भुगतान के चूक में कारावास की सजा का आदेश एक अलग आधार है। एक व्यक्ति को कारावास से गुजरना पड़ता है क्योंकि या तो वह जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ ह या इस तरह की राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है। इसलिए, जुर्माने का भुगतान न करने पर वह इस तरह की राशि का भुगतान करके हमेशा कारावास से बच सकता है। इसलिए, यह केवल शक्ति नहीं है, बल्कि अदालत का कर्तव्य भी है कि वह अपराधी को पूर्वनिर्धारीत कारावास भोगने का आदेश देने से पहले अपराध की प्रकृति, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, अपराधी की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखे।

32. आई.पी.सी. की धारा 63 से 70 में परीलक्षित कानून का एक सामान्य सिद्धांत यह जुर्माने है कि राशि कठोर या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। आई.पी.सी. के निर्माता इस समस्या के प्रति सचेत थे। अतः संहिता के लेखकों ने कहाः

"मृत्यु, कारावास, परिवहन, निर्वासन, एकांत, मजबूर श्रम, वास्तव में सभी पुरुषों के लिए समान रूप से अप्रिय नहीं हैं, लेकिन वे सभी मनुष्यों के लिए इतने अप्रिय हैं कि विधायिका, अपराधों के लिए इन दंडों को निर्धारित करते समय स्वभाव और स्थिति से उत्पन्न मतभेदों की सुरक्षित रूप से उपेक्षा कर सकती हैं। जुर्माने के मामले में स्थिति अलग है, जुर्माना लगाते समय अपराधी की और ्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध के चरित्र और परिमाण का भी उतना ही ध्यान रखना आवश्यक है।"

लेखकों ने आगे कहाः (रतनलाल और धीरजलाल पृष्ठ 226-27 पर)

..... जब जुर्माना लगाया गया है, तो भुगतान की चूक में होने पर क्या उपाय अपनाया जाएगा? और यहाँ आगे बढ़ने के दो तरीके, जिनसे हम परिचित थे, स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आए। जब तक जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, अपराधी को जेल हो सकती है या वह किसी निश्चित अवधि के लिए जेल जा सकता है, इस तरह के कारावास को जुर्माने के स्थान पर माना जाता है। पहले वाले मामले में, कारावास उसे

अपने पैसे छोडने के लिए मजबूर करने के लिए उपयोग किया जाता है; पूर्व के मामले में, कारावास एक प्रतिस्थापित सजा है। हमें लगता है कार्यवाही के दोनों तरीके कड़ी आपत्तियों के लिए खुले हैं। किसी अपराधी को जुर्माना अदा होने तक कारावास में रखना, यदि जुर्माना उसकी क्षमता से अधिक हो, तो उसे जीवन भर कारावास में रखना हैः और सर्वोत्तम न्यायाधीश के लिए यह सुनिश्चित करना असंभव है कि वह कभी-कभी ऐसा जुर्माना नहीं लगाएगा जो अपराधी की क्षमता से परे होगा।

..... दूसरी ओर, भुगतान न करने पर किसी अपराधी को जुर्माने और कारावास की एक निश्चित निश्चित अवधि के लिए सजा देना, और फिर यह निर्धारित करने के लिए उसे खुद पर छोड़ देना कि वह अपने पैसे के हिस्सा लेगा या जेल में रहेगा, हमारे लिए यह एक बहुत ही आपत्तिजनक मार्ग प्रतीत होता है.....

..... हम प्रस्ताव करते हैं कि जुर्माना लगाते समय न्यायालय जेल की एक निश्चित अवधि भी तय करेगा, जिसे भुगतान न करने पर अपराधी को भुगतना पड़ेगा।इस अवधि को तय करने में, न्यायालय को किसी भी मामले में एक निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो अपराध की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होगी। यदि अपराध ऐसा है जो कारावास के साथ-साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, तो भुगतान न करने पर कारावास की अवधि अपराध के लिए संहिता द्वारा निर्धारित

कारावास की सबसे लंबी अवधि की एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी। यदि अपराध ऐसा है जो संहिता संहिता के अनुसान केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो भुगतान में चूक के लिए कारावास की अवधि किसी भी स्थिती में सात दिनों से अधिक नहीं होगी।

33. कुछ मामलों में यह मुद्दा विचार के लिए भी आया, सम्राट बनाम मेंदी अली, ए.आई. और. 1941 ए. और इ. और इ. 310 एम. पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। हालांकि, सत्र अदालत ने उन्हें और इ.पी.सी. की धारा 304 भाग-एक तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि एम ने गंभीर और अचानक उकसावे में अपनी पत्नी की हत्या करने का अपराध किया था, क्योंकि जब उसने उसे (अपनी पत्नी को) अपनी आंखों से एन के साथ व्यभिचार करते हुए देखा था। इस प्रकार एम आत्म-नियंत्रण की शक्ति से पूरी तरह से वंचित हो गया। लेकिन सत्र न्यायाधीश ने धारा 304 भाग-एक के तहत न केवल अधिकतम दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, बल्कि 100 रुपये का जुर्माना या एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी दी।

34. एक स्वतः संज्ञान संशोधन में, उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायाधीश ने जिस अपराध के लिए एम को अधिकतम सजा सुनाई थी, जिसके लिए वह दोषी पाया गया था और इसमें एक जुर्माना जोड़ा गया था (जिसके भुगतान की निश्चित रूप से बहुत कम संभावना हो सकती थी)

परिणाम यह हुआ कि वास्तव में उसे ग्यारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

35. तथ्यों पर विचार करते हुए, जे. ब्रॉन्ड ने कहाः (मेंदी अली मामला, ए.आई. और पी. 311)

"जहाँ तक जुर्माने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि एक गरीब किसान के मामले में, एक बहुत ही दीर्घकालिक कारावास की सजा के साथ जुर्माना जोड़ना उचित होगा, जिसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भुगतान करने की उचित संभावना नहीं है और भुगतान करने में चूक होने पर उसे कारावास की अवधि भुगतनी होगी। और मेरे फैसले में, यह कहने का साहस किए बिना यह एक ऐसी कार्यप्रणाली है जो पूरी तरह से कानून के अनुरूप है या नहीं, मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि जहाँ कारावास की सजा भूगतनी पड़े, वहां इस तरह का जुर्माना लगाना और भी अवांछनीय हो जाता है। मुख्य रूप से कारावास की कुल सजा उस विशेष धारा द्वारा स्वीकृत कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक हो जाएगी, जिसके तहत उसे दोषी ठहराया जाता है। मैं यह सोचना साहस करता हूँ कि न्यायाधीशों को कारावास की लंबी अवधि की वास्तविक शर्तों पर जुर्माना लगाने के मामले में सावधानीपूर्वक विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

36. हम पलानीअप्पा गौंडर बनाम टी.एन. राज्य (1977) 2 एस.सी.सी. 634 में इस न्यायालय का भी उल्लेख कर सकते हैं।

उस मामले में, पी को प्रधान सत्र न्यायाधीश सलेम द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को मृत्युदंड से घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन सजा को कम करते हुए न्यायालय ने पी. पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने के औचित्य के सवाल तक सीमित इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई था।

37. न्यायालय ने और इ.पी.सी. और सी. और .पी.सी. के प्रावधानों पर भी विचार किया और पाया कि अदालतों को जुर्माना लगाने की शक्ति है और यदि किसी अपराधी पर जुर्माना लगाया जाता है, तो इसे कानून के विपरीत चुनौती नहीं दी जा सकती है।

38. न्यायालय की ओर से बोलते हुए, चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने कहाः **(एससीसी पीपी 638-39 , पैरा 9)**

"9. लेकिन वैधता को औचित्य के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए और तथ्य यह है कि न्यायालय के पास एक निश्चित शक्ति का मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा होना चाहिए। हालांकि, इसलिए उच्च न्यायालय के पास अपीलार्थी पर दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति थी। सवाल अभी भी उठता है कि क्या मामलें की परिस्थितियों में 20,000 रुपये की राशि के जुर्माने की सजा उचित है। और थिक अपराधों का आम तौर पर भारी जुर्माना लगाया जाता है क्योंकि एक अपराधी जिसने और थिक कानूनों का

उल्लंघन करके स्वयं को अनजाने में या अनुचित तरीके से समृद्ध किया है, तो उसे उस जुर्माने का भुगतान करने का साधन रखने को वैध रूप से माना जा सकता है। उसे गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को नष्ट करना होगा। लेकिन मामलों की व्यापकता में, वतर्मान प्रकार के मामलों पर काफी भिन्न विचार लागू होंगे। हालांकि मौत की सजा को जुर्माने की सजा के साथ जोड़ने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाता है क्योंकि मौत की सजा एक गंभीर दंड है और उस गंभीर दंड के साथ जुर्माने की सजा जोड़ने से शायद ही किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो पाती। वास्तव में, आम प्रवृत्ति में सजा का चलन यह है कि आजीवन कारावास की सजा के साथ शायद ही कभी जुर्माने की सजा को भी जोड़ा जाता है। हम निश्चित रूप कुछ मामलों में अपनाए गए अयोग्य दृष्टिकोण के अनुमोदन को व्यक्त करने के लिए इतनी दूर नहीं जा सकते कि हत्या का अपराध के लिए जुर्माने की सजा पूरी तरह से 'अनुचित' है (उदारहण के लिए, राज्य बनाम पांडुरंग तात्यासाहेब शिंदे ए. और ्इ. और . 1956 बोम. 711 पेरा-714 देखे), लेकिन मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा, विशेष रूप से भारी जुर्माना लगाने से पहले किसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जुर्माने की सजा आवश्यक है और यदि हां तो मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करने के लिए उचित या पर्याप्त जुर्माना क्या है। जैसा कि इस अदालत ने आदमजी उमर दलाल बनाम बॉम्बे राज्य, ए.आई. और. 1952 एस. सी. 14 में कहा था कि

सजा के सही मात्रा का निर्धारण अक्सर बड़ी कठिनाई का एक मुद्दा होता है और कोई कठाेर नियम नहीं हैं। यह एक विवेकाधिकार का मामला है जिसे विभिन्न प्रकार के विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना है, लेकिन न्यायालय को हमेशा अपराध और प्रस्तावित दंड के बीच एक अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता पर ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय के लिए बोलते हुए, महाजन, जे. ने उस मामले में कहा किः **(ए. और इ. और. पृष्ठ 16, पैरा 5)**

"5. ..... जुर्माना लगाते समय अभियुक्त व्यक्तियों की और ्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति और परिमाण का भी उतना ही ध्यान में रखना आवश्यक है, और जहाँ कारावास की पर्याप्त अवधि दी है, वहां अत्यधिक जुर्माना इसके साथ नहीं होना चाहिए, सिवाय असाधारण मामलों में"। लेकिन इस अदालत ने जुर्माने की सजा को 42,300 रुपये से घटाकर 4000 रुपये कर दिया, इस आधार पर कि निचली अदालत द्वारा जुर्माने की सजा अधिरोपण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर उचित ध्यान नहीं दिया था।

12. यह स्पष्ट है और दोहराया गया है कि जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की अवधि कोई सजा नहीं है। स्पष्ट रूप से कहे तो यह एक जुर्माना है जो जुर्माना न चुकाने वाले व्यक्ति पर लगता है। दूसरी और यदि सजा दी जाती है तो निस्संदेह, एक अपराधी को सजा भुगतनी होगी,

जब तक की न्यायिक कार्यवाही में इसे आंशिक या संपूर्ण रूप से संशोधित या परिवर्तित न किया जाए। हालांकि, जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास का आदेश एक अलग आधार है। जब इस तरह की पूर्वनिरधारित सजा दी जाती है, तो किसी व्यक्ति को कारावास से गुजरना पड़ता है क्योंकि या तो वह जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थ है या ऐसा भुगतान करने से इनकार करता है। तदनुसार, वह इतनी राशि का भुगतान करके जुर्माना न चुकाने पर कारावास से हमेशा बच सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा मानना है कि अपराध की प्रकृति जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, को ध्यान में रखना न्यायालय का कर्तव्य है। अपराधी को पूर्वनिर्धारित रूप से कारावास भुगतने का आदेश देने से पहले, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, अपराधी की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विचार जैसे कि अपराध के चरित्र और परिमाण के बारे में अभियुक्त व्यक्ति की और थिक परिस्थितियाँ व जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास के प्रावधान आई.पी.सी. की धारा 63 से 70 यह स्पष्ट करती है कि जुर्माने की राशि कठोर या अत्यधिक नहीं होना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि जहां कारावास की एक लम्बी अवधि लगाई जाती है, वहां अपवादात्मक मामलों को छोड़कर अत्यधिक जुर्माना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

13. उपरोक्त सिद्धांतों पर ध्यान देते हुए, हम इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान मामला स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

के तहत है और कुछ अपराधों के लिए, क़ानून ने न्यूनतम सजा के साथ-साथ न्यूनतम जुर्माना राशि का भी प्रावधान किया है। हमारे निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अपीलार्थी पहली बार के अपराधी थे, हमने विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित न्यूनतम सजा 15 वर्ष के बजाय वर्ष 10 दी थी। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थियों को 10 वर्ष के लिए और आई. की मूल सजा से गुजरने का आदेश दिया गया है, जो न्यूनतम है।

14. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 30 का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो जुर्माने न चुकाने पर कारावास की सजा के बारे में बात करती हैः

"30. जुर्माने अदा न करने पर कारावास की सजा-(1) मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास कि ऐसे अवधि प्रदान कर सकता है जो कानून के अनुसार अधिकृत हैः

बशर्ते कि अवधि

धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं है;

जहाँ कारावास को मूल सजा के हिस्से के रूप में दिया गया है, कारावास की अवधि का एक चौथाई भाग से अधिक नहीं होगा, जिसे मजिस्ट्रेट अपराध के लिए जुर्माने के भुगतान न करने की स्थिती में कारावास के रूप में दण्ड के रूप में देने मेंे सक्षम है।

इस धारा के तहत दिया गया कारावास धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णय योग्य अधिकतम अवधि के कारावास की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकता है।

यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 30 की उप-धारा (1) का खंड (बी) न्यायालय को कारावास की अवधि के 1/4 तक का जुर्माना चूक करने पर कारावास देने के लिए अधिकृत करती है, जिसे न्यायालय अपराध के लिए दंड के रूप में देने में सक्षम है। हालांकि, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों पर विचार करते हुए अर्थात, वे बहुत गरीब हैं और उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करना है, यह उनका पहला अपराध था और यदि वे आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जुर्माने का भुगतान करने में उनकी असमर्थता के कारण उन्हें मूल सजा की अवधि के अलावा 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए जेल में रहना होगा, हमारा मानना है कि न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्य जो निर्दोष हैं, के लिए भी गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। इसलिए हमारा मानना है कि न्याय का उद्देश्य तभी पूरा होगा,जब हम आदेश देते हैं कि डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलार्थियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अनुसार 3 साल के बजाय 6 महीने के लिए और .आई. से गुजरना होगा।

15. ऊपर बताए गए कारणों से, दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभिलिखित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और अपीलार्थियों को 15 वर्ष के लिए और. आई. से गुजरने की सजा को संशोधित कर 10 वर्ष कर दिया गया है। प्रत्येक पर 1.50 लाख रु. जुर्माने के भुगतान के आदेश को भी बरकरार रखा जाता है लेकिन यह आदेश कि जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलार्थियों को 3 साल के लिए और .आई. से गुजरना होगा, को घटाकर 6 महीने के लिए और .आई. कर दिया गया। चूंकि अपीलकर्ताओं ने पहले ही जेल में लगभग 12 साल बिताए हैं, इसलिए हमारा मानना है कि जुर्माने के भुगतान में चूक के संबंध में सजा की संशोधित अवधि के अनुसार, उन्हें जेल में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य अपराध में उनकी आवश्यकता न हो। यह आगे स्पष्ट किया जाता है किसी भी कारण से, यदि अपीलार्थियों ने सजा की संशोधित अवधि पूरी नहीं कि हैं, तो उन्हें यहां ऊपर बताई गई सजा की अवधि के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

16. अपीलों को उल्लिखित सीमा तक स्वीकार किया जाता है.....

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी और.के.मीणा (और.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।